

बजट2025-26 की मुख्य विशेषताएं (English at the end)

- भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में, मोदी सरकार के विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है।
 - इस सरकार के पहले दो कार्यकालों के दौरान किए गए परिवर्तनकारी कार्य एकमार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे यह सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हुई है।
- युवा, अन्नदाता और नारी (गरीब, युवा, किसान, महिला) पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।

आयकर्म राहत

- लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और आंग, विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में प्रमुख सहायक स्तंभ हैं। मध्यम वर्ग भारत के विकास को शक्ति प्रदान करता है।
 - माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता पर विश्वास किया है।
 - उनके योगदान को मान्यता देते हुए, सरकार ने समयसमय पर उनके करके बोझ को कम किया है। 2014 के ठीक बाद, 'शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर ₹2.5 लाख कर दिया गया, जिसे 2019 में बढ़ाकर ₹5 लाख और 2023 में ₹7 लाख कर दिया गया।
 - नई व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपये तककी आय अर्थात् पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आयको छोड़कर प्रति माह 1 लाख रुपये की औसत आय पर कोई आयकर्म नहीं देना होगा।
 - वेतनभोगी वर्ग के लिए, ₹12.75 लाख की वार्षिक आयकर्म कोई आयकर्म नहीं है, क्योंकि वेतनभोगी वर्ग को ₹75,000 का मानक कटौती लाभ उपलब्ध है।
- विभिन्न आयस्तरों पर स्लैब दर में परिवर्तन और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है।
 - नई व्यवस्था में ₹12 लाख की आय वाले करदाता को कर में ₹80,000 का लाभ मिलेगा (मौजूदा दरों के अनुसार देय कर का 100% छूट प्राप्त होगा)। प्रभावी आयकर दर 0% होगी।
 - ₹16 लाख की आय वाले व्यक्ति को कर में ₹50,000 का लाभ मिलेगा। [देय प्रभावी आयकर दर सिर्फ 7.5% होगी]
 - ₹18 लाख की आय वाले व्यक्ति को कर में ₹70,000 का लाभ मिलेगा। [देय प्रभावी आयकर दर सिर्फ 8.8% होगी]

- 20 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को कर में 90,000 रुपये का लाभ मिलेगा । [देय प्रभावी आयकर दर सिर्फ 10% होगी]।
- 25 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा । [प्रभावी कर दर सिर्फ 13.2% होगी]
- 50 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को भी 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा । [प्रभावी कर दर सिर्फ 21.6% होगी]

इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का राजस्व छूट जाएगा।

चित्रण

आय	स्लैब औदरों पर कर		लाभ	छूट लाभ (12 लाख रुपये से कम आय वालों के लिए)	कुल लाभ	लाभ के बाद कर
	उपस्थित	प्रस्तावित				
			दर/स्लैब	12 लाख रुपये तक की पूर्ण छूट		
8 लाख तक	30,000	20,000	10,000	20,000	30,000	0
9 लाख	40,000	30,000	10,000	30,000	40,000	0
10 लाख	50,000	40,000	10,000	40,000	50,000	0
11 लाख	65,000	50,000	15,000	50,000	65,000	0
12 लाख	80,000	60,000	20,000	60,000	80,000	0
16 लाख	1,70,000	1,20,000	50,000	0	50,000	1,20,000
20 लाख	2,90,000	2,00,000	90,000	0	90,000	2,00,000
24 लाख	4,10,000	3,00,000	1,10,000	0	1,10,000	3,00,000
50 लाख	11,90,000	10,80,000	1,10,000	0	1,10,000	10,80,000

संशोधित करस्लैब (वित्त वर्ष 2025-26)	
0-4 लाख रुपए	शून्य
4-8 लाख रुपए	5 प्रतिशत
8-12 लाख रुपए	10 प्रतिशत
12-16 लाख रुपए	15 प्रतिशत
16-20 लाख रुपए	इसे स्वीकार करो
20- 24 लाख रुपए	25 प्रतिशत
24 लाख रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

प्रमुख घोषणाएं

- सरकार ' **प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना** ' शुरू करेगी राज्यों के साथ साझेदारी में।
 - इस योजना के अंतर्गत **कमउत्पादकता, मध्यम फसलघनता औरऔसत्त कमऋणमानकों** वाले 100 जिले शामिल होंगे। इससे 1.7 करोड़ किसानों को मददमिलेगी।
- तुर, उड़द औरसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 साल का “ **दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन** ” शुरू करेगी।
 - इसमें उत्पादकता में सुधार, घरेलू दाल उत्पादन,

पर

- **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)** 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों औरखेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। **संशोधित ब्याज सहायता योजना** के तहत ऋणके लिए **केसीसी ऋण सीमा ₹3 लाखसे बढ़ाकर ₹5 लाख की जाएगी ।**
- राज्यों के साथ साझेदारी में एकव्यापक बहु-क्षेत्रीय ' **ग्रामीण समृद्धि औरसूचीलापन** ' कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
 - इससे कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के माध्यम से कृषि में अल्प-रोजगार की समस्या का समाधान किया जाएगा।
 - इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसरपैदा करना है ताकि प्रवास एकविकल्प हो, लेकिन अनिवार्यता नहीं ।
 - चरण1 में 100 विकासशील कृषि जिलों को कवरकिया जाएगा ।
- शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एकनई योजना लागू की जाएगी, जिससे उनकी आयमें सुधार हो सके, उन्हें स्थायी आजीविका मिल सके औरजीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सके।
- सरकार **गिग वर्कर के पहचान पत्र औरई- श्रम पोर्टल पर पंजीकरण** की व्यवस्था करेगी। **प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना** के तहत गिग वर्करों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी । इस उपाय से लगभग 1 करोड़ गिग-वर्करों को सहायता मिलने की संभावना है ।
- को सरकार, बैंकों औरनिजी निवेशकों के योगदान से एकमिश्रित वित्त सुविधा के रूप में **स्थापित किया जाएगा । ₹15,000 करोड़ के इसफंड का लक्ष्य अन्य 1 लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करना होगा।**
 - SWAMIH ने 50,000 आवासीय इकाइयां तैयार कर ली हैं। 2025 में 40,000 औरइकाइयां तैयार हो जाएंगी।

- ऋणकपहूंच में सुधार के लिए , **ऋणगारंटी कवरको बढ़ाया जाएगा :**
 - a) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋणसीमा को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है , जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋणपलब्ध होगा।
 - b) स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक, आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 फोकसक्षेत्रों में ऋणके लिए गारंटी शुल्क को घटाकर 1 प्रतिशत किया गया ।
 - c) अच्छी तरह से संचालित निर्यातक एमएसएमईके लिए 20 करोड़ रुपये तकके सावधि ऋण।
- **पर्यटन क्षेत्र में शीर्ष 50 पर्यटन स्थल** भारत में रोजगार आधारित विकास को चुनौती मोड के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। रोजगार आधारित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:
 - आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों सहित हमारे युवाओं के लिए **गहनकौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना**
 - होमस्टे के लिए **मुद्रा ऋणपलब्ध कराना**
 - पर्यटक सुविधाओं, स्वच्छता और विपणन प्रयासों सहित **प्रभावी गंतव्य प्रबंधन के लिए राज्यों को प्रदर्शन-संबंधी प्रोत्साहन प्रदान करना**
 - **सुव्यवस्थित ई-बीजा सुविधाएं शुरू करना ।**
- एमएसएमईको उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन औरसूजी तकबेहतर पहुंच प्राप्त करने में मददकरने के लिए , सभी एमएसएमईके वर्गीकरण के लिए **निवेश औरस्टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और गुना तकबढ़ाया जाएगा ।**

इससे उन्हें आगे बढ़ने औरहमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का आत्मविश्वास मिलेगा।

Rs. in Crore	Investment		Turnover	
	Current	Revised	Current	Revised
Micro Enterprises	1	2.5	5	10
Small Enterprises	10	25	50	100
Medium Enterprises	50	125	250	500

- **'निर्यात संवर्धन मिशन' की स्थापना की जाएगी**जिसे वाणिज्य, एमएसएमई औरवित्त मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। इससे निर्यात ऋणसीमा पार फैक्ट्रिंग सहायता औरएमएसएमईको सहायता तकआसान पहुंच की सुविधा मिलेगी।
- **संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री शुरू की जाएगी ।** हम केवाईसी के आवधिक अद्यतन के लिए एकसुव्यवस्थित प्रणाली भी लागू करेंगे।

- मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी ।
- उच्च उपजवाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया जायेगा।
- लाखों कपास उत्पादक किसानों के लाभ के लिए ' कपास उत्पादकता मिशन' शुरू करेंगे ।
 - यह 5-वर्षीय मिशन कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा तथा अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देगा।
- भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) औसच्च सागरों से मत्स्य पालन के सततदोहन के लिए एकसक्षम ढांचा लाएगी , जिसमें अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- असमके नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा ।
- एकबड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा ।
 - विश्वकर्मा , नए उद्यमियों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, एमएसएमई और बड़े व्यापारिक संगठनों की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा ।

उद्यमिता, एमएसएमई और रोजगार

- सरकार उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले 'कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड' शुरू करेगी । पहले वर्ष में ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।
- 10,000 करोड़ रुपये के योगदान के साथ एकनया फंड ऑफंड्स स्थापित किया जाएगा।
- महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 'पहली बार उद्यमी' बनने वालों के लिए एकनई योजना शुरू की जाएगी ।
 - इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तकका टर्म लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
- फुटवियर औसचमड़ा क्षेत्र के लिए एकफोकस उत्पाद योजना लागू की जाएगी । इसयोजना से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने, 4 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने और 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है ।
 - घरेलू मूल्य संवर्धन और रोजगार के लिए आयात को सुविधाजनक बनाने हेतु वेट ब्लू लेदर पर मूल सीमा शुल्क अबपूरी तरह से छूट दी गई है ।
- घरेलू मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन में सुधार लाने तथा सौर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर और नियंत्रक, इलेक्ट्रोलाइजर , पवन टर्बाइन, अति उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और गिड स्केल

बैटरी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए **स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को समर्थन देगी**।

- वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ कौशल विकास के लिए **5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र** स्थापित किए जाएंगे।

निवेश

A. लोगों में निवेश

- सक्षम **आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम** यह योजना देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है। **पोषण सहायता के लिए लागत मानदंडों को उचित रूप से बढ़ाया जाएगा**।
- अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में **50,000 अटल टिकरिंग लैब** स्थापित की जाएंगी।
- **ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी (भारत नेट)** ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा
- **भारतीय भाषा पुस्तक योजना** स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए एक नई पहल शुरू की जाएगी।
- शुरू किए गए **5 आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा वर्ष 2014 के बाद 6,500 और अधिक छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है**। (पिछले 10 वर्षों में 23 आईआईटी में छात्रों की कुल संख्या 65,000 से 1.35 लाख तक 100 प्रतिशत बढ़ गई है।)
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता केंद्र** शिक्षा के लिए **500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक कॉलेज** स्थापित किया जाएगा।
- अगले वर्ष **मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी**, अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य है। (सरकार ने 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख यूजी और पीजी मेडिकल शिक्षा सीटें जोड़ी हैं, जो 130 प्रतिशत की वृद्धि है।)
- अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में **डे केयर कैंसर सेंटर** स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

शहरी आजीविका और शहरी विकास

- पीएम स्वनिधि का पुनर्गठन किया जाएगा बैंकों से ऋणमें वृद्धि, 30,000 रुपये की सीमा के साथ यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता।
- प्रस्तावों को लागू करने के लिए ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष जुलाई के बजट में 'विकास केन्द्र के रूप में शहर , ' शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' और ' जल एवं स्वच्छता' के लिए योजनाओं की घोषणा की गई थी।
 - ₹10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस निधि के लिए 2025-26 हेतु प्रस्तावित बजट।

B. अर्थव्यवस्था में निवेश

- राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋणके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन ।
- नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी लगाने के लिए दूसरी परिसंपत्ति मुद्राकरण योजना 2025-30 शुरू की जाएगी।
- जलजीवन मिशन का 2028 तक विस्तार "जन भागीदारी " के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और रखरखाव के लिए कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है।
- सरकार राज्यों द्वारा बिजली वितरण सुधारों और अंतर-राज्यीय पारेषण क्षमता में सुधार को प्रोत्साहित करेगी । इससे बिजली कंपनियों की वित्तीय सेहत और क्षमता में सुधार होगा। इन सुधारों के आधार पर राज्यों को जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी ।
- एकपरमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा । 2033 तक कमसे कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित एसएमआय हो जाएंगे।
- जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति जहाज निर्माण क्षेत्र में लागत संबंधी नुकसान को दूर करने के लिए इसमें सुधार किया जाएगा।
- समुद्री उद्योग के दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए 25,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना की जाएगी ।
- अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी ।
- पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम रियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा ।

- सरकार ने कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रेप, सीसा, जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को पूरी तरह से छूट देने का प्रस्ताव किया है। इससे भारत में विनिर्माण के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने और हमारे युवाओं के लिए अधिक नौकरियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

- ऐसे ओपनसेल के विनिर्माण को और बढ़ावा देने के लिए, इन भागों पर बीसीडी से अब छूट मिल जाएगी।

- सरकार ने ईवी बैटरी विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत सामान और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत सामान जोड़ने का प्रस्ताव किया है। इससे मोबाइल फोन और ईवी के लिए लिथियम-आयन बैटरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

C. नवप्रवर्तन में निवेश

- जुलाई बजट में घोषित निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान, विकास और संचालन पहल को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- इस पहल के एक भाग के रूप में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रेरित करने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की भी संभावना तलाशी जाएगी।
- अगले 5 वर्षों में, पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत हम बड़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान करेंगे।
- 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों वाला दूसरा जीन बैंक भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए एक योजना स्थापित की जाएगी।
- राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन शुरू करेंगे आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा का विकास करना।
- हमारी पाण्डुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ मिलकर एक ज्ञान भारत मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पाण्डुलिपियों को शामिल किया जाएगा।

निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास

- एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, 'भारत ट्रेड नेट' (बीटीएन) की स्थापना की जाएगी, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा।

- **वैश्विक क्षमता केन्द्रों (जीसीसी) को बढ़ावा देने** के लिए एकराष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी, जो उभरते हुए द्वितीय श्रेणी के शहरों में जीसीसी स्थापित करने के लिए राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करेगी।
- **सरकार एयर कार्गो के लिए बुनियादी ढांचे और गोदाम के उन्नयन की सुविधा प्रदान करेगी** इसमें उच्च मूल्य वाले शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पाद भी शामिल हैं।
- **हस्तशिल्प के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए** सरकार ने निर्यात की समयावधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी है।
- सरकार ने एक नया प्रावधान पेश किया है, जिससे आयातकों या निर्यातकों को माल की निकासी के बाद, **स्वेच्छा से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा करने तथा ब्याज सहित, लेकिन बिना जुर्माने के, शुल्क का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी।** इससे स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा।

सुधार

- पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधार लागू किए हैं, जैसे:
 - फेसलेस असेसमेंट, करदाता चार्टर, तीव्र रिटर्न, लगभग 99 प्रतिशत रिटर्न स्व-मूल्यांकन पर आधारित होना तथा विवाद से विश्वास योजना।

इन सुधार प्रयासों को जारी रखते हुए:

- **बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी।** यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं।
- **ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' विकसित करेंगे** यह स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा।
- **पेंशन उत्पादों के विनियामक समन्वय और विकास के लिए एक मंच स्थापित किया जाएगा।**
- **एक उच्च स्तरीय समिति** सभी गैर-वित्तीय क्षेत्र के विनियमनों, प्रमाणनों, लाइसेंसों और अनुमतियों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की जाएगी
- **राज्यों का निवेश मित्रता सूचकांक 2025 में लॉन्च किया जाएगा।**
- **मौजूदा वित्तीय नियमों और सहायक निर्देशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा।**
- **जनविश्वास विधेयक 2.0** लाया जाएगा। (जनविश्वास अधिनियम 2023 के तहत 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया था।)

अन्य कर सुधार

- वर्तमान में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए कोई समयसीमा प्रदान नहीं करता है, जिससे अनिश्चितता और व्यापार की लागत बढ़ जाती है। व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में, सरकार ने अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए दो साल की समयसीमा तय की है, जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है।
- वर्तमान में करदाता केवल कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही स्व-कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा कर सकते हैं। करदाताओं की कठिनाइयों को देखते हुए, सरकार ने अब बिना किसी शर्त के 2 ऐसी स्व-कब्जे वाली संपत्तियों का लाभ उठाने की अनुमति दी है।
- व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और वार्षिक जांच का विकल्प प्रदान करने के लिए, सरकार ने 3 साल की ब्लॉक अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की आर्म्स लेंथ कीमत निर्धारित करने की एक योजना शुरू की है। यह वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होगा।
- मुकदमेबाजी को कम करने और अंतरराष्ट्रीय कराधान में निश्चितता प्रदान करने के उद्देश्य से, सेफ हार्बर नियमों का दायरा बढ़ाया जा रहा है।
- उन अनिवासियों के लिए एक अनुमानित कराधान व्यवस्था प्रदान की है जो किसी ऐसी निवासी कंपनी को सेवाएं प्रदान करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित या संचालित कर रही है।
- वर्तमान में टन भार कर योजना केवल समुद्र में जाने वाले जहाजों के लिए उपलब्ध है। देश में अंतर्देशीय जलपरिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर योजना का लाभ भारतीय पोत अधिनियम, 2021 के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जहाजों को भी देने का प्रस्ताव है।
- सरकार ने 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित होने वाले स्टार्टअप्स को लाभ उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप्स के निगमन की अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।
- IFSC में अतिरिक्त गतिविधियों को आकर्षित करने और बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने IFSC में स्थापित वैश्विक कंपनियों के जहाज-पट्टे वाली इकाइयों, बीमा कार्यालयों और ट्रेजरी केंद्रों को विशेष लाभ देने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, लाभों का दावा करने के लिए, IFSC में आरंभ करने की कटऑफ तिथि को भी पाँच वर्ष बढ़ाकर 31.3.2030 कर दिया गया है।
- वर्तमान में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए कोई समयसीमा प्रदान नहीं करता है, जिससे अनिश्चितता और व्यापार की लागत बढ़ जाती है। व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में, सरकार ने अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए दो साल की समयसीमा तय करने का प्रस्ताव किया है, जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है।

- आरबीआई की उदारिकृत विप्रेषण योजना (एलआरएफके तहत विप्रेषण पर स्रोत पर कर(टीसीएस) एकत्र करने की सीमा को ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने का प्रस्ताव है ।
- सरकार ने शिक्षा प्रयोजनों के लिए प्रेषित धनपर टीसीएस हटाने का प्रस्ताव किया है , जहां ऐसा प्रेषित धन किसी निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋणसे हो।
- 2022 में उनकरदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन के लिए अद्यतन रिटर्न सुविधा लाई, जो अपनी सही आयकी रिपोर्ट करना भूल गए थे।
 - करदाताओं पर सरकार का भरोसा सही साबित हुआ । करीब 90 लाख करदाताओं ने स्वैच्छा से अतिरिक्त करदेकर अपनी आयपडेट की।
 - यह है किसी भी करनिर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को वर्तमान 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है ।
- कई वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के पास बहुत पुराने राष्ट्रीय बचत योजना खाते हैं। चूंकि ऐसे खातों पर अब ब्याज नहीं मिलता है, इसलिए सरकार ने 29 अगस्त, 2024 को या उसके बाद व्यक्तियों द्वारा एनएसएस की गई निकासी को छूट देने का प्रस्ताव दिया है ।
 - सरकार ने एनपीएस वात्सल्य खातों के लिए भी समान करउपचार की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है, जो सामान्य एनपीएस खातों के लिए उपलब्ध है , जो समग्र सीमाओं के अधीन है।

HighlightsofBudget 2025-26

- **India's economy is the fastest-growing among all major global economies.** Over the past 10 years, Modi Govt's development track record and structural reforms have garnered significant international attention.
 - The transformative work during this Government's first 2 terms serves as a guiding light, enabling this govt to move forward with determination.

- In this Budget, the proposed development measures span across various sectors focusing on Garib, Yuva, Annadata and Nari. (Poor, Youth, Farmers, Women)

Income Tax Relief

- Democracy, Demography and Demand are the key support pillars in our journey towards Viksit Bharat. **The middle class provides strength for India's growth.**
 - Hon'ble Prime Minister Modi led NDA Govt has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building.
 - In recognition of their contribution, **Govt periodically has reduced their tax burden. Right after 2014, the 'Niltax' slab was raised to ₹2.5 lakh, which was further raised to ₹5 lakh in 2019 and to ₹7 lakh in 2023.**
 - **In this Budget Govt has announced that there will be No Income Tax payable upto income of ₹12 lakh** (i.e. average income of ₹1 lakh per month other than special rate incomes such as capital gains) **under the new regime.**
 - **For the Salaried Class, No Income Tax is applicable till annual income of ₹12.75 lakh, due to standard deduction benefit available to salaried class of ₹75,000.**
- The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with examples.
 - **A taxpayer in the new regime with an income of ₹12 lakh will get a benefit of ₹80,000 in tax** (100% of tax payable as per existing rates will be exempt). The effective income tax rate will be 0%.
 - **A person having income of ₹16 lakh will get a benefit of ₹50,000 in tax.** [The effective income tax rate payable will be just 7.5%]
 - **A person having income of ₹18 lakh will get a benefit of ₹70,000 in tax.** [The effective income tax rate payable will be just 8.8%]
 - **A person having income of ₹20 lakh will get a benefit of ₹90,000 in tax.** [The effective income tax rate payable will be just 10%].
 - **A person with an income of ₹25 lakh gets a benefit of ₹1,10,000.** [The effective tax rate will be just 13.2%]
 - **A person with an income of ₹50 lakh also gets a benefit of ₹1,10,000.** [The effective tax rate will be just 21.6%]

As a result of these proposals, revenue of about ₹ 1 lakh crore in indirect taxes will be forgone.

Illustration

Income	Tax on Slabs and rates		Benefit of	Rebate benefit (for those earning below Rs.12 lakh)	Total Benefit	Tax after benefit
	Present	Proposed				
Upto 8lakh	30,000	20,000	10,000	20,000	30,000	0
9lakh	40,000	30,000	10,000	30,000	40,000	0
10lakh	50,000	40,000	10,000	40,000	50,000	0
11lakh	65,000	50,000	15,000	50,000	65,000	0
12lakh	80,000	60,000	20,000	60,000	80,000	0
16lakh	1,70,000	1,20,000	50,000	0	50,000	1,20,000
20lakh	2,90,000	2,00,000	90,000	0	90,000	2,00,000
24lakh	4,10,000	3,00,000	1,10,000	0	1,10,000	3,00,000
50lakh	11,90,000	10,80,000	1,10,000	0	1,10,000	10,80,000

Revised Tax Slabs (FY 2025-26)	
0-4 lakhruppes	Nil
4-8 lakhruppes	5 percent
8-12 lakhruppes	10 percent
12-16 lakhruppes	15 percent
16-20 lakhruppes	20 percent
20- 24 lakhruppes	25 percent
Above 24 lakhruppes	30 percent

Key Announcements

- Government will undertake a **‘Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana’** in partnership with states.

- This scheme will cover **100** districts with low productivity, moderate crop intensity and below-average credit parameters. It will help **1.7** crore farmers.
- Govt will now launch a 6-year **“Mission for Aatmanirbhar in Pulses”** with a special focus on Tur, Urad and Masoor.
 - It will focus on improving productivity, domestic pulses production, assuring remunerative prices to the farmers and development of climate resilient seeds.
- **Kisan Credit Cards (KCC)** facilitates short term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. **The KCC loan limit will be enhanced from ₹3 lakh to ₹5 lakh** for loans under the Modified Interest Subvention Scheme.
- A comprehensive **multi-sectoral ‘Rural Prosperity and Resilience’** programme will be launched in partnership with states.
 - This will address **under-employment in agriculture** through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy.
 - **The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option, but not a necessity.**
 - **In Phase-1, 100** developing agri-districts will be covered.
- A **new scheme for socio-economic upliftment of Urban Workers** will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods and a better quality of life.
- Govt will arrange for **Gig Worker’s** identity cards and registration on the **e-Shram** portal. Gig workers will be provided **healthcare under PM Jan Arogya Yojana**. **This measure is likely to assist nearly 1 crore gig-workers.**
- **SWAMIH Fund 2** will be established as a **blended finance facility** with contribution from the Government, banks and private investors. **This fund of ₹15,000 crore will aim for expeditious completion of another 1 lakh units.**
 - SWAMIH has delivered 50,000 dwelling units. Another 40,000 units will be completed in 2025.
- **To improve access to credit, the Credit Guarantee Cover will be enhanced:**
 - d) **For Micro and Small Enterprises, from ₹5 crore to ₹10 crore,** leading to additional credit of ₹1.5 lakh crore in the next 5 years.
 - e) **For Startups, from ₹10 crore to 20 crore,** with the guarantee fee being moderated to 1 percent for loans in 27 focus sectors important for Atmanirbhar Bharat.
 - f) **For well-run exporter MSMEs, for term loans up to ₹20 crore.**
- **In the Tourism sector, Top 50** **tourist destination sites** in India will be developed in partnership with states through a

challenge mode. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth:

- **Organizing intensive skill-development programmes** for our youth including in Institutes of Hospitality Management
- **Providing MUDRA loans** for homestays
- **Providing performance-linked incentives** to states for effective destination management including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts
- **Introducing streamlined e-visa facilities.**
- **To help MSMEs achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively.**

This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth.

Rs. in Crore	Investment		Turnover	
	Current	Revised	Current	Revised
Micro Enterprises	1	2.5	5	10
Small Enterprises	10	25	50	100
Medium Enterprises	50	125	250	500

- **'Export Promotion Mission'** to be set up which will be driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, and support to MSMEs.
- **The revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025 for simplifying KYC process.** We will also implement a streamlined system for periodic updating of KYC.
- Presently, the **Customs Act, 1962** does not provide any time limit to finalize Provisional Assessments leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, Govt has fixed a time limit of two years, extendable by a year, for finalising the provisional assessment.
- To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases, **Govt has proposed to add 36 lifesaving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from Basic Customs Duty (BCD).**
 - Govt also proposed to add **6 lifesaving medicines to the list attracting concessional customs duty of 5%.** Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above.

- **New Income Tax Bill to be introduced in the Budget session.** The New Income Tax Bill will be clearer and will have around 50% lesser text compared to the present law, in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administration, leading to tax certainty and reduced litigation.

Key Highlights

Improving Agricultural Growth and Rural Development

- A **Makhana Board** will be established in Bihar to improve production, processing, value addition, and marketing of makhana.
- A **National Mission on High Yielding Seeds** will be launched.
- We will undertake '**Mission for Cotton Productivity**', for the benefit of lakhs of cotton growing farmers.
 - This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming, and promote extra-long staple cotton varieties.
- **Government will bring in an enabling Framework for sustainable harnessing of Fisheries from Indian Exclusive Economic Zone (EEZ) and High Seas,** with a special focus on the Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.
- A **Urea plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons** will be set up at Namrup, Assam.
- **India Post will also be transformed as a large public logistics organization.**
 - This will meet the rising needs of Viswakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and large business organizations.

Entrepreneurship, MSMEs & Employment

- **The Govt will introduce 'Customized Credit Cards' with a ₹5 lakh limit for Micro Enterprises registered on Udyam portal.** In the first year, 10 lakh such cards will be issued.
- A new **Fund of Funds for Startups**, with a contribution of ₹10,000 crore will be set up.
- A new scheme will be launched for **5 lakh women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes 'First-time entrepreneurs'.**
 - This will provide Term Loans up to ₹2 crore during the next 5 years.
- For **India's footwear and leather sector,** a focus products scheme will be implemented. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate turnover of ₹4 lakh crore and exports of over ₹1.1 lakh crore.
 - **Basic Custom duty on Wet Blue leather is now fully exempt** to facilitate imports for domestic value addition and employment.
- **Govt will support Clean Tech manufacturing** to improve domestic value addition, jobs and build a ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers,

electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries.

- **5 National Centres of Excellence for Skilling will be set up** with global expertise and partnerships.

Investments

D. Investing in people

- The **Saksham Anganwadi and Poshan programme** provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the north-east region. **The cost norms for the nutritional support will be enhanced appropriately.**
- **50,000 Atal Tinkering Labs will be set up** in Government schools in next 5 years.
- **Broadband connectivity** (BharatNet) will be provided to all Government secondary schools and primary health centres in rural areas.
- **Bharatiya Bhasha Pustak Scheme** will be introduced to provide digital form Indian language books for school and higher education.
- **Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014** to facilitate education for 6,500 more students. (Total number of students in 23 IITs has increased 100 percent from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years.)
- **A Centre of Excellence in Artificial Intelligence** for education will be set up with a total outlay of ₹500 crore.
- **In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges** and hospitals, towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. (Govt has added almost 1.1 lakh UG and PG medical education seats in 10 years, an increase of 130 percent.)
- **Govt will facilitate setting up of Day Care Cancer Centres in all district hospitals** in the next 3 years. **200 Centres will be established in 2025-26.**

Urban livelihood and Urban Development

- **PM SVANidhi will be revamped** with enhanced loans from banks, UPI linked credit cards with ₹30,000 limit, and capacity building support.
- **Urban Challenge Fund of ₹1 lakh crore** to implement the proposals for 'Cities as Growth Hubs', 'Creative Redevelopment of Cities' and 'Water and Sanitation' announced in the July Budget.
 - **An allocation of ₹10,000 crore** is proposed for 2025-26 for this fund.

E. Investing in Economy

- An outlay of ₹1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loan to states for capital expenditure and incentives for reforms.
- Second Asset Monetization Plan 2025-30 will be launched to plough back capital of ₹10 lakh crore in new projects.
- Extension of the Jal Jeevan Mission until 2028 with an enhanced total outlay for quality of infrastructure and maintenance of rural pipe water supply schemes through “Jan Bhagidhari”
- Govt will incentivize Electricity Distribution reforms and improvement of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5 percent of GSDP will be allowed to states, contingent on these reforms.
- A Nuclear Energy Mission for research & development of Small Modular Reactors (SMR) with an outlay of ₹20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed SMRs will be operationalized by 2033.
- The Shipbuilding Financial Assistance Policy will be revamped to address cost disadvantages in the shipbuilding sector.
- For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of ₹25,000 crore will be set up.
- A modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years.
- Financial support will be provided for the Western Koshi Canal ERM Project benefitting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar.
- Govt has proposed to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, Lead, Zinc and 12 more critical minerals. This will help secure their availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth.
 - To further boost the manufacture of such Open Cells, the BCD on these parts will now stand exempted.
- Govt has proposed to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing, and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion battery, for mobile phones & EVs.

F. Investing in Innovation

- Govt has allocated ₹20,000 crore to implement private sector driven Research, Development and Innovation initiative announced in the July Budget.
- A Deep Tech Fund of Funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative.

- In the next 5 years, under the **PM Research Fellowship scheme**, we will provide **10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc** with enhanced financial support.
- The **2nd Gene Bank with 10 lakh germplasm lines** will be set up for future food and nutritional security.
- We will start a **National Geospatial Mission** to develop foundational geospatial infrastructure and data.
- A **Gyan Bharatam Mission for survey, documentation and conservation of four Manuscript Heritage** with academic institutions, museums, libraries and private collectors will be undertaken to cover more than **1 crore manuscripts**.

Efforts for promoting Exports

- A digital public infrastructure, '**Bharat Trade Net**' (BTN) for international trade will be set up as a **unified platform for trade documentation and financing solutions**
- A National Framework for **promoting Global Capability Centres (GCCs)** will be formulated as a guideline to states to set up GCCs in emerging tier 2 cities.
- **Govt will facilitate upgradation of infrastructure and Warehousing for Air Cargo** including high value perishable horticulture produce.
- **To facilitate exports of Handicrafts**, Govt has extended the time period for export from 6 months to 1 year.
- Govt has introduced a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to **voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivise voluntary compliance.**

Reforms

- Over the past **10** years, our Government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as:
 - faceless assessment, taxpayers charter, faster returns, almost **99** percent returns being on self-assessment, and Vivadse Vishwas scheme.

Continuing these reform efforts:

- **The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100 percent.** This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India.
- **Public Sector Banks will develop 'Grameen Credit Score'** framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas.
- **A forum for regulatory coordination and development of pension products** will be set up.

- A **High-Level Committee for Regulatory Reforms** will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions
- An **Investment Friendliness Index of States** will be launched in 2025.
- Under the **FSDC (Financial Stability and Development Council)**, a mechanism will be set up to **evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions.**
- **Jan Vishwas Bill 2.0** will be brought to decriminalize more than 100 provisions in various laws. (Under Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized.)

Other Tax Reforms

- Presently, the **Customs Act, 1962** does not provide any time limit to finalize Provisional Assessments leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, Govt has fixed a time limit of two years, extendable by a year, for finalising the provisional assessment.
- Presently tax-payers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfilment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, **Govt now has allowed the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition.**
- **To streamline the process of transfer pricing** and to provide an alternative to yearly examination, Govt has introduced a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices.
- With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, **the scope of Safe Harbour Rules is being expanded.**
- Govt has provided a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility.
- Presently the tonnage tax scheme is available to only seagoing ships. **The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act, 2021** to promote inland water transport in the country
- **Govt has proposed to extend the period of incorporation of Startups by 5 years** to allow the benefit available to start-ups which are incorporated before 1.4.2030.
- In order to attract and promote additional activities in the IFSC, Govt has proposed specific benefits to ship-leasing units, insurance offices and treasury centres of global companies which are set up in IFSC. Further,

to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by five years to 31.3.2030.

- Presently, the Customs Act, 1962 does not provide any time limit to finalize Provisional Assessments leading to uncertainty and cost to trade. **As a measure of promoting ease of doing business, Govt has proposed to fix a time-limit of two years, extendable by a year, for finalising the provisional assessment.**

Measures in Indirect Taxation

- As a part of comprehensive review of Customs rate structure announced in July 2024 Budget, Govt has proposed to:
 - **Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 2023-24 budget.** After this, there will be only 8 remaining tariff rates including 'zero' rate. (
 - **Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence except on a few items,** where such incidence will reduce marginally.
 - **Levy not more than one cess surcharge.** Therefore, It is proposed to exempt Social Welfare Surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess.
- Specified drugs and medicines under Patient Assistance Programmes run by pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to patients. **Govt has proposed to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programmes.**
- For industry to better plan their imports, Govt has proposed to extend the time limit for the end-use of imported inputs in the relevant rules, from six months to one year.
 - This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement.

Measures in Direct Taxation

- **New Income Tax Bill to be introduced in the Budget session.** The new bill will be clear and around 50% lesser text compared to the present law, in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administration, leading to tax certainty and reduced litigation.
- **The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present ₹50,000 to ₹1 lakh.**
- **Annual limit of ₹2.40 lakh for TDS on rent is being increased to ₹6 lakh.** This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments.

- The threshold to collect tax at source (TCS)
on remittances under RBI's Liberalized Remittance Scheme (LRS)
is proposed to be increased from ₹7 lakh to ₹10 lakh.
- Govt has proposed to Remove TCS on Remittances for Education Purposes, where such remittance is out of a loan taken from a specified financial institution.
- Govt brought the **Updated return facility in 2022**
for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income.
 - Govt's trust in taxpayers was proved right. Nearly 90
lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax.
 - It is proposed to extend the time-limit to file updated returns for any assessment year, from the current limit of 2 years, to 4 years.
- A number of senior and very senior citizens have very old National Savings Scheme accounts. As interest is no longer payable on such accounts, therefore **govt has proposed to exempt withdrawal made from NSS by individual son or after the 29th of August, 2024.**
 - Govt also has proposed to allow similar Tax treatment to NPS
Vatsalya accounts as is available on normal NPS accounts, subject to overall limits.